परिणामी बजट वर्ष 2023-24

विभाग- वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालनालय,उद्योग

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2023-24	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
1	मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना	राज्य के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना	30100	600 शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराना	
2	उद्योगों को ब्याज अनुदान	लघु व मध्यम-वृहद नवीन उद्योगों की स्थापना तथा उद्योग के विस्तार हेतु वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से लिये गये सावधि ऋण एवं/या कार्यशील पूंजी पर ब्याज अनुदान देकर उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बनाना	440000	1850 प्रकरणों में अनुदान का लाभ देना	
3	नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना	नये औद्योगिक क्षेत्रों के अंतर्गत सेलर जिला-बिलसपुर, चिरंगा जिला-सरगुजा, केसदा जिला-बलौदाबाजार, अभनपुर जिला-रायपुर की स्थापना हेतु । औद्योगिक क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास कार्य	1050000	1. 04 नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना 2. 10 औद्योगिक क्षेत्रों में ऑनगोइंग वर्क अंतर्गत अधोसंरचना विकास कार्य	
4	औद्योगिक इकाईयों को लागत पूंजी अनुदान	नवीन उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिये अनुदान	1280000	568 लघु उद्योगों को अनुदान	
5	औद्योगिक क्षेत्र में अधोसंरचनात्मक उन्नयन कार्य	प्रदेश में स्थापित औद्योगिक क्षेत्र/संस्थानों में सड़क एवं नालियों के निर्माण/मरम्मत एवं विद्युतिकरण व जलप्रदाय तथा अधोसंरचना का विकास करना	151500	सड़क एवं नाली, बी.टी. सड़क का रिनिवल कोर्ट, सी.सी.रोड, औद्योगिक क्षेत्रों का विकास।	
6	ग्रामीण उद्यमी विकास योजना प्रशिक्षण	नवीन उद्योगों की स्थापना के लिये आवश्यक कुशलता को विकसित करने हेतु राज्य के युवा उद्यमियों को प्रशिक्षण दिया जाता है	1500	700 ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित करना	
7	फूड पार्क की स्थापना	राज्य के समन्वित औद्योगिक विकास हेतु फूड पार्क की स्थापना	500000	राज्य के विभिन्न जिलों में फूडपार्क हेतु	

परिणामी बजट वर्ष 2023-24

विभाग- वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालनालय,उद्योग

राशि हजार ₹ में

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	बजट प्रावधान 2023-24	क्वांटिफायेबल डिलीवरेबल्स	टिप्पणियां
8	छ.ग. औद्योगिक योजना नीति के अंतर्गत प्रतिपूर्ति अनुदान	औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत विभिन्न इकाईयों को उनके अतिरिक्त निवेश पर एम.ओ.यू. अंतर्गत छूट/रियायतें/सुविधाये आदि हेतु अनुदान प्रदान किये जाने हेतु	1500000	30 औद्योगिक इकाईयों को अनुदान	
9	औद्योगिक पार्को के लिये अनुदान	राज्य के समन्वित औद्योगिक विकास के लिए विभिन्न पार्को की स्थापना हेतु	50000	प्लास्टिक पार्क 19.173 हेक्टेयर	